फा.सं. 1704813/1/2022-मा. (समन्वय) (ई-21449)
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग
ग्राउंड फ्लोर, 36, जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक 13 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मत्स्यपालन विभाग द्वारा जनवरी, 2024 माह के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों और महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार मंत्रिमंडल सचिवालय को परिचालित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/1/2018-कैब का संदर्भ लेने और जनवरी, 2024 माह के लिए मत्स्यपालन विभाग का मासिक सारांश परिचालित करने का निदेश हुआ है जिसमें की गई प्रमुख गतिविधियां,महत्वपूर्ण निर्णय और मंत्रिमंडल समिति/ समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रगति सूचनार्थ संलग्न है।

यथोक्त: संलग्नक

(डॉ. एन्सी मैथ्यू एनपी)
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)

प्रति
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य

प्रतिलिपि

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001 (ध्यानार्थ: श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक)
2. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
3. राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
5. प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
7. सलाहकार, कृषि कार्यक्षेत्र, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली

सूचना के लिए प्रतिलिपि:

1. माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के निजी सचिव
2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. सचिव, मात्स्यिकी के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
5. मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी डीओएफ को विभाग की वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेज अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में जनवरी, 2023 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां

1. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला ने 27 जनवरी, 2024 को कोटेश्वर (कोरी क्रीक), कच्छ, गुजरात में समुद्री शैवाल (सी वीड) की खेती को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की । उन्होंने इस बात पर महत्त्व दिया कि समुद्री शैवाल की खेती दृढ़ता से की जानी चाहिए क्योंकि इसमें मत्स्य किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन बढ़ाने, पारंपरिक मत्स्यन पर निर्भरता कम करने और तटीय समुदायों की आजीविका में विविधता लाने की क्षमता है । केंद्रीय मंत्री ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रदर्शनी में फिशरीज़ स्टार्ट-अप, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) – मात्स्यिकी संस्थानों, मात्स्यिकी महाविद्यालयों आदि द्वारा लगाए गई विभिन्न समुद्री शैवाल स्टालों का दौरा किया । मत्स्य किसानों, मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया । केंद्रीय मंत्री ने कोरी क्रीक में समुद्री शैवाल पायलट गतिविधियों के लिए मोनोकलाइन, ट्यूब नेट और राफ्ट पद्धति का भी निरीक्षण किया।

2. मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के 250 लाभार्थियों और विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मछुआरों को उनके जीवनसाथी के साथ गणतंत्र दिवस परेड, 2024 को देखने के लिए कर्तव्य पथ, नई दिल्ली पर आमंत्रित किया। इन सम्मानित अतिथियों ने 26 जनवरी, 2024 को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखी। परेड के बाद, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में इन विशेष आमंत्रित लोगों के साथ बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया।

3. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने 17 जनवरी, 2024 को पूसा, नई दिल्ली में मात्स्यिकी और जलीय कृषि बीमा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रमुख वैश्विक अनुभवों, मात्स्यिकी/जलीय कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय मंत्री ने दावेदार लाभार्थियों को प्रत्येक को 5 लाख के समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के चेक भी वितरित किए। सम्मेलन में मत्स्य किसानों, मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और उत्पादक कंपनियों, मात्स्यिकी प्रबंधन में शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों, ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया।

4. सागर परिक्रमा चरण X का नेतृत्व माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला और डॉ. एल. मुरुगन, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में किया। परिक्रमा 01 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के जुवेल्डिन फिशिंग हार्बर से शुरू हुई और 6 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, यानम जिला (पुदुच्चेरी केंद्र शासित प्रदेश) को कवर करते हुए समाप्त हुई। सागर परिक्रमा के दौरान, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए गए, नाव/जाल, आइस बॉक्स के साथ दोपहिया वाहन जैसी संपत्ति वाले पीएमएमएसवाई लाभार्थियों को सम्मानित किया गया और नव नियुक्त सागर मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएमएमएसवाई लाभार्थियों जैसे मछुआरा महिलाओं, मछुआरों, जलीय किसानों और अन्य हितधारकों और उनके संघों के साथ एक बातचीत सत्र भी आयोजित किया गया था ।

5. सागर परिक्रमा चरण XI माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला द्वारा 7 से 9 जनवरी 2024 के दौरान ओडिशा के तटीय जिलों अर्थात् गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर जिले में किया गया था जिसके बाद प्रत्येक इलाके में पीएमएमएसवाई लाभार्थियों जैसे मछुआरा महिलाओं, मछुआरों, जलीय किसानों और अन्य हितधारकों और उनके संघों के साथ बातचीत की गई। माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए परियोजना की आधारशिला भी रखी।

6. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने 10 जनवरी, 2024 से 11 जनवरी, 2024 तक पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा चरण-XII को पूरा किया । इसने तटीय क्षेत्रों जैसे दीघा, शंकरपुर फिशिंग हार्बर, गंगा सागर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर (सीआईबीए) के काकद्वीप अनुसंधान केंद्र को कवर किया।

7. माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 06 जनवरी, 2024 को आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के बोगापुरम मंडल के चेरुकुपल्ली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया।

8. मत्स्यपालन विभाग के सचिव ने 3 जनवरी, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ खारे पानी के झींगा जलीय कृषि की क्षमता की समीक्षा की।